NYCS

RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com

फरवरी 2026, नई दिल्ली

सहकारिता भरेगी नई उड़ान

अंदर के पन्नों पर

- मैन्युफैक्चरिंग-एसएमई पर फोकस से बढ़ेगा रोजगार
- तीन साल में देशभर में दौड़ने लगेगी भारत टैक्सी

पंडित आदित्य पारीक

चौथी पीढ़ी के ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ

पंडित आदित्य पारीक

एपी ग्रुप की स्थापना (2011) से लेकर आज तक, **पंडित आदित्य पारीक** उसके पीछे की अडिग शक्ति के रूप में खड़े हैं। वे पारंपरिक आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक नवाचार के अद्वितीय संगम का सजीव उदाहरण हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और सिविल इंजीनियरिंग की मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, पंडित आदित्य पारीक ने अवसंरचना विकास की परिवर्तनकारी शक्ति को समय रहते पहचान लिया और अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता तथा अटूट संकल्प के बल पर अपने उद्यम को वैश्विक पहचान दिलाई।

किन्तु उनका व्यक्तित्व केवल एक सफल उद्योगपति तक सीमित नहीं है। एक चौथी पीढ़ी के ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ के रूप में वे अपने नेतृत्व में अपनी आध्यात्मिक परंपरा की दिव्यता को समाहित करते हैं। वे केवल भवनों का निर्माण नहीं करते, बल्कि जीवनों को संवारते हैं और ऐसी विरासत का निर्माण करते हैं जो पीढ़ियों तक प्रेरणा देती है।

मध्य प्रदेश की विनम्र धरती से उभरकर आए पंडित आदित्य पारीक का सफर किसी विशेष सुविधा या संसाधन से सुसज्जित नहीं था। मात्र 500 रुपये की पूंजी और बिना किसी संरक्षक के उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत की। प्रारंभिक दिनों में परिस्थितियाँ इतनी चुनौतीपूर्ण थीं कि दो समय का भोजन भी एक विलासिता जैसा प्रतीत होता था। बी.टेक की डिग्री प्राप्त करने के बावजूद उनका उद्देश्य किसी के अधीन नौकरी करना नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर अपने परिवार और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देना था।

> "पंडित आदित्य पारीक और एपी ग्रुप की दूरदर्शी यात्रा"

अथक परिश्रम, धैर्य और अडिग विश्वास के बल पर उन्होंने एक छोटे से अवसर को सफलता की आधारशिला में परिवर्तित कर दिया। आज एपी ग्रुप उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और नेतृत्व क्षमता का जीवंत प्रमाण है, जिसमें फाइवटेक, ग्लैमरे सॉल्यूशंस, एपी एस्ट्रो, एपी इंटीरियर एंड डिजाइन सहित 18 से अधिक संस्थाएँ सम्मिलित हैं और जो 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं।

फिर भी, पंडित आदित्य पारीक की दृष्टि सीमित नहीं है। उनकी सोच व्यापक है, उनके लक्ष्य उच्च हैं और उनका संकल्प समाज, राष्ट्र और आध्यात्मिक चेतना के समग्र उत्थान के लिए निरंतर अग्रसर है।

निशिका ए. पारीक एक समर्पित वास्तु इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जो सौंदर्य और ऊर्जा के संतुलन को अपने प्रत्येक प्रोजेक्ट की आधारशिला मानती हैं। वे पारंपरिक वास्तु सिद्धांतों को आधुनिक इंटीरियर डिज़ाइन के साथ सहज रूप से जोड़ते हुए ऐसे स्थानों का सृजन करती हैं, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा, संतुलन और समृद्धि का प्रवाह स्वाभाविक रूप से महसूस होता है। उनके डिज़ाइन केवल आकर्षक नहीं होते, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक समझ पर आधारित होते हैं,

युवा सहकार

वर्ष : 02, अंक-08, फरवरी-2026

निदेशक मंडल

एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं इम्प्रेसन्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18-19-20, सेक्टर-59, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी द्वारा मुद्रित।

कार्यकारी संपादक: अभिषेक कुमार
पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

भविष्य पर नजर 04
कौशल विकास के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से एमओयू 05

06 आम बजट 2026-27 सहकारिता भरेगी नई उड़ान

18 दिल्ली में बनेगी महिला कोऑपरेटिव सोसायटी

तीन साल में देशभर में दौड़ने लगेगी भारत टैक्सी 20
स्टार्टअप इंडिया का एक दशक 24
एनवाईसीएस का विशेष सेवा अभियान 26
भविष्य के सितारे: वैभव, आयुष और विहान 28
उत्तराखंड की सहकारी समितियां सुरक्षा बलों को मुहैया करा रहीं रसद व डेयरी उत्पाद 30

भविष्य पर नजर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में तात्कालिक और लोकलुभावन घोषणाओं की बजाय लंबी अवधि को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई हैं। खासकर मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई (मध्यम, छोटे एवं लघु उद्यम), महिला उद्यमिता, पर्यटन और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने वाले सहकारिता, डेयरी एवं पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले जो प्रावधान किए गए हैं उससे रोजगार बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग को गति देने से घरेलू स्तर पर वस्तुओं का निर्माण बढ़ेगा जिससे निवेश एवं रोजगार में वृद्धि के साथ आयात में कमी आएगी और निर्यात बढ़ेगा। ग्लोबल अनिश्चितता के इस दौर में आर्थिक विकास दर की गति को तेज बनाए रखने के लिए एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना जरूरी है।

आम बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। सहकारिता क्षेत्र के आवंटन में जहां 77.78 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र के लिए टैक्स में दी गई विशेष छूट से सहकारी संस्थाओं को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को मिली 450 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से सहकारी कृषि निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी जिसका लाभ अंततः सहकारिता क्षेत्र को ही मिलेगा।

भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इस गति को निरंतरता देने के लिए आम बजट में इन दोनों क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए है जिसका असर लंबी अवधि में दिखेगा। रोजगारपरक सात मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, रेयर अर्थ, केमिकल, कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल क्षेत्र पर फोकस किए जाने से इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर की दुनियाभर में बढ़ती मांग के बीच निर्मला सीतारमण ने इस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

इसी तरह कृषि, सहकारिता, डेयरी एवं पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र ग्रामीण समृद्धि का आधार है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों को सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दी है। 2026-27 के बजट में इन क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। कृषि क्षेत्र के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। सहकारिता क्षेत्र के आवंटन में जहां 77.78 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हुई है, वहीं इस क्षेत्र के लिए टैक्स में दी गई विशेष छूट से सहकारी संस्थाओं को फायदा मिलेगा। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 2,761.80 करोड़ रुपये का बजटीय का प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के बजट में भी 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो अब 6,153 करोड़ रुपये हो गया है। यह अब तक का इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा आवंटन है। मत्स्य पालन और पशुपालन में उद्यमिता को बढ़ावा देने से गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

वित्त वर्ष 2026-27 का कुल बजट 53.5 लाख करोड़ रुपये का है। इस दौरान सरकार की आमदनी 36.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। बाकी 17.2 लाख करोड़ रुपये का खर्च बाजार से उधार लेकर किया जाएगा। इस वर्ष राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रोजगार बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्री ने आम बजट में जो कवायद की है वह सही दिशा में उठाया गया कदम तो है, लेकिन इससे पहले के वर्षों में रोजगार को लेकर जो योजनाएं लागू की गई थीं उनकी स्थिति पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। नहीं तो मंशा साफ होने के बावजूद लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। उदाहरण के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए शुरू की गई पीएलआई स्कीम और पीएम इंटर्नशिप योजना को ले सकते हैं जिनके अपेक्षित नतीजे नहीं मिल रहे हैं। ऐसी योजनाओं की समीक्षा कर उनकी कमियों को दूर करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

कौशल विकास के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से एमओयू

भविष्य के रोजगारपरक कार्यों के लिए तैयार किया जाएगा विश्व स्तरीय कार्यबल

युवा सहकार टीम

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इसका मकसद भारत के कौशल और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इस एमओयू पर स्विटजरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक में हस्ताक्षर किया गया।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से मंत्रालय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग करेगा ताकि भारत में एक स्किल्स एक्सीलरेटर लॉन्च और लागू किया जा सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक वैश्विक बहु-हितधारक मंच है जो कार्यबल में महत्वपूर्ण कौशल कमियों को पूरा करने के लिए नए समाधानों, सार्वजनिक-निजी साझेदारियों की पहचान और विस्तार का उद्देश्य रखता है। स्किल्स एक्सीलरेटर देश के तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन करेगा जिससे कौशल पहलों और उद्योग एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकसित होती मांगों के बीच संपर्क सुनिश्चित होगा।

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने इस उपलब्धि पर कहा, 'भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को भविष्य के काम के साथ जोड़ने के लिए जो रणनीतिक दृष्टिकोण शुरू हुआ था, उसने अब एक व्यवस्थित और ग्लोबल रूप ले लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी में इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर को औपचारिक रूप देना भविष्य के लिए तैयार विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी कार्यबल बनाने में एक अहम पड़ाव है। सरकार, उद्योग और शिक्षा को एक साथ लाकर यह पहल वर्तमान और उभरते कौशल अंतराल को दूर करने, परिणाम आधारित कौशल वित्त पोषण को सक्षम बनाने तथा आजीवन सीखने और वैश्विक श्रम बाजार मांग के साथ तालमेल को बढ़ावा देने के लिए समन्वित कार्रवाई को मजबूत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विजन इंडिया@2047 के अनुरूप यह समावेशी विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन का केंद्रीय स्तंभ बनाते हुए कौशल को मजबूत करता है।'

यह पहल भारत की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में एक्सीलरेटर कौशल के लिए नवीन वित्त पोषण तंत्रों का समर्थन करेगा, प्रमुख हितधारकों के बीच रणनीतिक समन्वय सक्षम करेगा तथा विभिन्न उद्योगों और नौकरी भूमिकाओं में उभरते वैश्विक मांग और आपूर्ति रुझानों की पहचान करेगा ताकि अंतरराष्ट्रीय रोजगारशीलता को बढ़ाया जा सके। इसके तहत भविष्य के कार्य के उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और उन्नत विनिर्माण शामिल हैं। एमओयू के कार्यान्वयन की निगरानी एक शासन ढांचे के माध्यम से की जाएगी जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र के लोग शामिल होंगे।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय स्किल्स एक्सीलरेटर की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने, हितधारक संलग्नता का समन्वय करने तथा उद्योग, सरकार और नागरिक समाज में पहल को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। साथ ही निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन तंत्रों में योगदान देगा। इसमें विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की भी भागीदारी है जो कौशल और व्यावसायिक शिक्षा एजेंडे को वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं। इस साझेदारी के माध्यम से सुधारों को तेज करने, वैश्विक संबंधों को मजबूत बनाने तथा भारत को कौशल, प्रतिभा और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। इससे आने वाले दशकों में लचीली, समावेशी और भविष्य तैयार कार्यबल बनाया जाएगा। ■

आम बजट 2026-27

सहकारिता भरेगी नई उड़ान

सहकारिता क्षेत्र के बजट में 77.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 1,744.74 करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त वर्ष 2025-26 में सहकारिता क्षेत्र का बजट 981.31 करोड़ रुपये था

एक सहकारी समिति को दूसरी सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश पर टैक्स में छूट मिलेगी, बशर्ते वह इसे आगे अपने सदस्यों में वितरित कर दे

युवा सहकार टीम

सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का जो संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है, उसकी बानगी आम बजट में लगातार दिखती रही है। खासकर, सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में कभी कोई कसर नहीं रखी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी सेक्टर को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो बजटीय आवंटन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन्हें शामिल करना इसलिए भी जरूरी है कि फिशरीज और डेयरी कोऑपरेटिव को अभी इसी क्षेत्र में गिना जाता है। ये सभी क्षेत्र गांवों और किसानों से जुड़े हैं और इनके सशक्तीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है।

सहकारी संस्थाएं अब ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली नई ताकत बनकर उभर रही हैं। खासतौर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) अब गांवों में रोजगार, सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रही हैं। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाने का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है उसे पूरा करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में न सिर्फ नए प्रावधान किए हैं, बल्कि

सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। सहकारिता क्षेत्र के बजट में जहां करीब 78 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, वहीं पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के बजट में करीब 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को संसद में दिए अपने बजट भाषण में सहकारिता क्षेत्र के लिए डिजिटल आधुनिकीकरण, सहकारी संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उन्हें टैक्स में राहत देने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के बजट में 77.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 1,744.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में यह बजट 981.31 करोड़ रुपये था। इससे पैक्स के साथ डेयरी, तिलहन, फल, बागवानी फसलों में सहकारिता को बढ़ावा मिलेगा और इनसे जुड़े पैक्स को मजबूत किया जाएगा। इसी तरह मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 2,761.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के बजट में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो अब 6,153 करोड़ रुपये हो गया है। यह अब तक का इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा आवंटन है। वित्त वर्ष 2025-26 में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए 4,850 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। वित्त वर्ष 2026-27 का कुल बजट 53.5 लाख करोड़ रुपये का है यानी इस वर्ष केंद्र सरकार का कुल खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि आमदनी 36.5 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। बाकी 17.2 लाख करोड़ रुपये बाजार से उधार यानी कर्ज लिए जाएंगे। इस वर्ष राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2025-26 में जीडीपी का 4.4 प्रतिशत अनुमानित था।

वित्त मंत्री ने प्राथमिक सहकारी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव किया है। यह बजट किसानों और सहकारी समितियों को राहत देने वाला है। पशुचारा और कपास

यह बजट 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की ऊंची उड़ान का आधार है। कृषि, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मत्स्य पालन और पशुपालन में उद्यमिता को बढ़ावा देने से गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। बजट में नारियल, काजू, कोको और चंदन के उत्पादन में लगे किसानों के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। भारत विस्तार एआई टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में जानकारी उपलब्ध कराकर उनकी बहुत मदद करेगा। यह बजट महत्वाकांक्षी है और राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

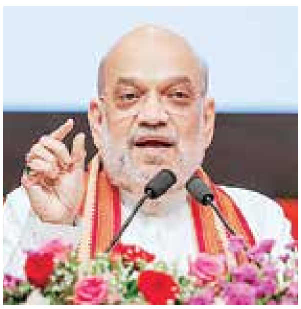

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है, जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। यह बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

बीज की आपूर्ति पर कटौती की अनुमति से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे उनकी लागत कम होगी और आमदनी बढ़ेगी। साथ ही, स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) से छूट से सहकारी संस्थाओं को अतिरिक्त वित्तीय राहत मिलेगी, जिससे वे अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद करेगा और कृषि क्षेत्र में निवेश एवं उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सहायक साबित होगा। सहकारी समितियों के माध्यम से मछुआरों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी बजट में एक अहम कदम उठाया गया है। अब भारतीय जहाजों को एक्सक्लूसिव इकॉनोमिक जोन (ईईजेड) या खुले समुद्र में पकड़ी गई मछलियों पर कोई शुल्क नहीं देगा पड़ेगा। इन मछलियों को अगर विदेशी बंदरगाह पर उतारा जाता है, तो इसे निर्यात माना जाएगा। इस पहल से मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों को आर्थिक मजबूती, नए बाजारों तक पहुंच और सहकारिता से समृद्धि का सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम सहकारी ढांचे को मजबूत कर ग्रामीण और मछुआरा समुदाय की प्रगति की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा।

ऊंची उड़ान का आधारः पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'यह बजट 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की ऊंची उड़ान का आधार है। कृषि, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मत्स्य पालन और पशुपालन में उद्यमिता को बढ़ावा देने से गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। बजट में नारियल, काजू, कोको और चंदन के उत्पादन में लगे किसानों के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। भारत विस्तार एआई टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में जानकारी उपलब्ध कराकर उनकी बहुत मदद करेगा। यह बजट महत्वाकांक्षी है और राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है।' उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को भविष्योन्मुखी, संवेदनशील बजट और गांवों, गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित बजट पेश करने के लिए बधाई दी।

विकसित भारत के निर्माण का बजटः अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है, जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। यह बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक, हर गाँव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के सपनों को शक्ति देकर उन्हें पूरा करने वाला बजट है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण और अगले 25 वर्षों के रोडमैप को दर्शाने वाले इस बजट के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी और और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हर भारतवासी की ओर से हार्दिक अभिनंदन।'

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि बजट 2026-27 समावेशी विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और सामाजिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह देश के बुनियादी ढांचे, तकनीक, उद्योग, कृषि और युवाओं के भविष्य को एक साथ सशक्त करने वाला बजट है।

टैक्स में राहत

मोदी सरकार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर सहकारी समिति लाभांश आय पर टैक्स राहत देने की घोषणा की है। यह सहकारी समितियों के लिए दोहरे कराधान को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है।

इसके तहत एक सहकारी समिति को दूसरी सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश पर टैक्स में छूट मिलेगी, बशर्ते वह इसे आगे अपने सदस्यों में वितरित कर दे। इससे सहकारी संस्थाओं के पास अधिक पूंजी बचेगी और व्यक्तिगत सदस्यों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी। इसी तरह राष्ट्रीय सहकारी संघों द्वारा 31 जनवरी, 2026 तक कंपनियों में किए

MINISTRY OF FINANCE | pib | केन्द्रीय बजट 2026-27

प्रमुख आंकड़े

₹ करोड़ में	2024-25 (वास्तविक)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (संशोधित अनुमान)	2026-27 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां	3,03,6619	34,20,409	33,42,323	35,33,150
पूंजी प्राप्तियां	16,16,249	16,44,936	16,22,519	18,14,165
कुल प्राप्तियां	46,52,867	50,65,345	49,64,842	53,47,315
कुल व्यय	46,52,867	50,65,345	49,64,842	53,47,315
प्रभावी पूंजीगत व्यय	13,24,609	15,48,282	14,03,906	17,14,523
राजस्व घाटा	5,64,296	5,23,846	5,26,764	5,92,344
प्रभावी राजस्व घाटा	2,91,640	96,654	21,8,613	99,642
राजकोषीय घाटा	15,74,431	15,68,936	15,58,492	16,95,768
प्राथमिक घाटा	4,58,856	2,92,598	28,4154	2,91,796

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) को 450 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य एनसीईएल को एक निर्यातक के रूप में प्रतिस्पर्धी बनाना है। सहकारी कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि निर्यात का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए एनसीईएल की स्थापना की गई है।

गए निवेश से मिलने वाले लाभांश पर तीन वर्षों तक टैक्स छूट दिया गया है। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस व्यवस्था से सहकारी ढांचे में मध्यस्थता कम होगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। जब अतिरिक्त आमदनी सीधे सदस्य समितियों तक पहुंचेगी, तो वह अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं, अधिक अवसर और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकेंगी। इससे किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा।

एनसीईएल को मिले 450 करोड़ रुपये

केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) को 450 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य एनसीईएल को एक निर्यातक के रूप में प्रतिस्पर्धी बनाना है। सहकारी कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि निर्यात का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए एनसीईएल की स्थापना की गई है। कृषि निर्यात में बड़े घरेलू व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहले से मौजूदगी है। ऐसे में इन निर्यात कंपनियों से एनसीईएल को प्रतिस्पर्धा करनी है। इसी उद्देश्य से सरकार ने एनसीईएल को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। देश भर की कृषि सहकारी समितियां इसकी सदस्य बन रही हैं, जिससे निर्यात से होने वाली आमदनी का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सकेगा।

पैक्स का आधुनिकीकरण और विस्तार

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही पैक्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है जिसे इस बजट में भी जारी रखा गया है। देश के 67 हजार से ज्यादा पैक्स के कंप्युटरीकरण के लिए बजट आवंटन जारी रखा गया है ताकि पारदर्शिता बढ़े। पैक्स अब केवल ऋण देने तक ही सीमित नहीं हैं। इन्हें खाद-बीज वितरण, अनाज भंडारण, जन औषधि केंद्रों, सीएससी, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर और पेट्रोल पंपों के संचालक के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। 2027 तक हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले संसद में पेश किए 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया है कि सहकारी क्षेत्र में बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण किया गया है जिससे पैक्स ने पारदर्शिता और भरोसे की नई पहचान बनाई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने 67,930 पैक्स के कंप्युटरीकरण को मंजूरी दी जिसके लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। इसके तहत 54,150 पैक्स ईआरपी सॉफ्टवेयर से जुड़ चुकी हैं,

जबकि 43,658 पैक्स पूरी तरह डिजिटल रूप से लाइव हो चुके हैं। सहकारी क्षेत्र का डिजिटलीकरण होने से लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ी है और युवाओं का भरोसा सहकारी संस्थाओं पर मजबूत हुआ है।

इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य है कि हर पंचायत में कम से कम एक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था हो। इस दिशा में मार्च 2025 तक 18,183 नई सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर बन रहे हैं। अनाज भंडारण में पैक्स की अहम भूमिका को आर्थिक सर्वेक्षण में रेखांकित करते हुए बताया गया है कि 500 पैक्स में नए गोदामों का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे किसानों को फसल के बाद नुकसान से राहत मिलेगी और उन्हें सही समय पर बेहतर दाम मिल सकेंगे।

खेती को हाईटेक बनाने की तैयारी

वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को पारंपरिक पद्धति से निकालकर आधुनिक और हाईटेक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी घोषणा भारत विस्तार नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफार्म की शुरुआत करने की है। वित्त मंत्री ने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत तक है। एआई आधारित भारत विस्तार का उद्देश्य किसानों को सीधे उनके मोबाइल पर मौसम की सटीक जानकारी, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण और फसलों के लिए हर मौसम में समय समय पर सलाह उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल 'एग्री-स्टैक' के साथ एकीकृत होगा, जिससे किसानों की पहचान और उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता का पारदर्शी रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। भारत विस्तार जैसी पहल केवल किसानों को जानकारी नहीं देगी, बल्कि सहकारी संस्थाओं को ज्ञान और डाटा की ताकत प्रदान करेगी। जब एक ही इलाके के किसान, एफपीओ, सहकारी समिति और स्वयं सहायता समूह एक साझा डिजिटल मंच पर जुड़ेंगे, तो निर्णय व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होंगे। इससे लागत घटेगी, उत्पादन सुधरेगा और सौदेबाजी की ताकत बढ़ेगी।

उच्च-मूल्य वाली फसलों पर विशेष ध्यान देने की बात वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयात कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशिष्ट फसलों पर फोकस किया है। इसमें उन फसलों की खेती पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिससे किसानों को अधिक आमदनी हो सकती है। इनमें नारियल, काजू और कोको शामिल हैं। इन फसलों की पैदावार और निर्यात बढ़ाने के लिए नए प्रोत्साहन

आम बजट 2026-27

- **वित्त वर्ष 2026-27 का कुल बजट 53.5 लाख करोड़ रुपये का है, आमदनी 36.5 लाख करोड़ रुपये अनुमानित**
- **17.2 लाख करोड़ रुपये बाजार से उधार लिए जाएंगे, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान**
- **सहकारिता क्षेत्र का बजट 981.31 करोड़ रुपये से बढ़कर हुआ 1,744.74 करोड़ रुपये**
- **राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को मिली 450 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता**
- **सहकारी समितियों और संघों को निवेश पर मिलने वाले लाभांश पर मिली टैक्स छूट**
- **पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का बजट बढ़कर 6,153 करोड़ रुपये पर पहुंचा, अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन**
- **अब निजी क्षेत्र भी खोल सकेंगे वेटनरी कॉलेज, हॉस्पिटल, टेस्टिंग लैब और पशु प्रजनन केंद्र**
- **मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता राशि 2,761.80 करोड़ रुपये प्रस्तावित, 500 नए जलाशय होंगे विकसित**
- **खेती बनेगी हाईटेक, भारत विस्तार नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफार्म की होगी शुरुआत**
- **सात मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, रेयर अर्थ, केमिकल, कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल को बढ़ावा**
- **इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का बजट, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की होगी शुरुआत**
- **छोटे और मझोले उद्यमों को सस्ती वित्तीय सहायता देने को एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का पैकेज**

आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी घोषणा भारत विस्तार नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफार्म की शुरुआत करने की है। एआई आधारित भारत विस्तार का उद्देश्य किसानों को सीधे उनके मोबाइल पर मौसम की सटीक जानकारी, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण और फसलों के लिए हर मौसम में समय समय पर सलाह उपलब्ध कराना है।

2026-27 के केंद्रीय बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय सहायता राशि 2,761.80 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है। कुल आवंटन में से 2,530 करोड़ रुपये योजना आधारित उपायों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिससे मछुआरों और मछली पालकों को प्रत्यक्ष सहायता सुनिश्चित होगी।

कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। बागवानी का कायाकल्प किये जाने का प्रावधान है। पुराने बागानों को आधुनिक तकनीक से सुधारने और अखरोट, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स की खेती का दायरा बढ़ाने के लिए विशेष फंड दिया गया है। चंदन और अगर जैसे कीमती पेड़ों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में योजनाएं पेश की गई हैं।

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति

सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति के ढांचे को लागू करना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सहकारी बैंकों और समितियों में पेशेवर प्रबंधन और शासन सुधार के लिए मानक तय किए गए हैं। ओडिशा जैसे कई राज्यों ने अपनी नीतियों को केंद्र की इस नई नीति के साथ जोड़ दिया है ताकि छोटे किसानों और कारीगरों को बेहतर ऋण और बीमा सुविधा मिल सके। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत सहकारी क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए बजट में अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही सहकारी मॉडल के माध्यम से डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में 'स्मार्ट क्लस्टर' विकसित करने की योजना है।

मजबूत होगी नीली अर्थव्यवस्था

मत्स्य पालन क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री ने 500 नए जलाशयों को विकसित करने का बजट में प्रावधान किया है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में इन नए जलाशयों और अमृत सरोवरों को व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए आम बजट में ड्यूटी-फ्री फिशिंग का प्रावधान किया

गया है। भारतीय जहाजों द्वारा गहरे समुद्र में पकड़ी गई मछलियों को शुल्क मुक्त लैंडिंग की अनुमति दी गई है, जिससे समुद्री खाद्य निर्यात बढ़ेगा। 2026-27 के केंद्रीय बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय सहायता राशि 2,761.80 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है। कुल आवंटन में से 2,530 करोड़ रुपये योजना आधारित उपायों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिससे मछुआरों और मछली पालकों को प्रत्यक्ष सहायता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) मत्स्य पालन विकास का मुख्य आधार बनी हुई है, जिसके लिए वर्ष 2026-27 में 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो लगभग तीन करोड़ लोगों, विशेष रूप से सीमांत और तटीय समुदायों के लोगों की आजीविका का आधार है। एक उभरते हुए सेक्टर के रूप में मान्यता प्राप्त मत्स्य पालन ने हाल के वर्षों में उत्पादन, निर्यात, अवसंरचना विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए नीतिगत उपायों के माध्यम से निरंतर वृद्धि दर्ज की है। पिछले एक दशक में भारत के मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वार्षिक मछली उत्पादन में 106 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 197.75 लाख टन हो गया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि प्रमुख विकास चालक के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने इसी अवधि में 147 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। यह 61.36 लाख टन से बढ़कर 151.60 लाख टन हो गया है।

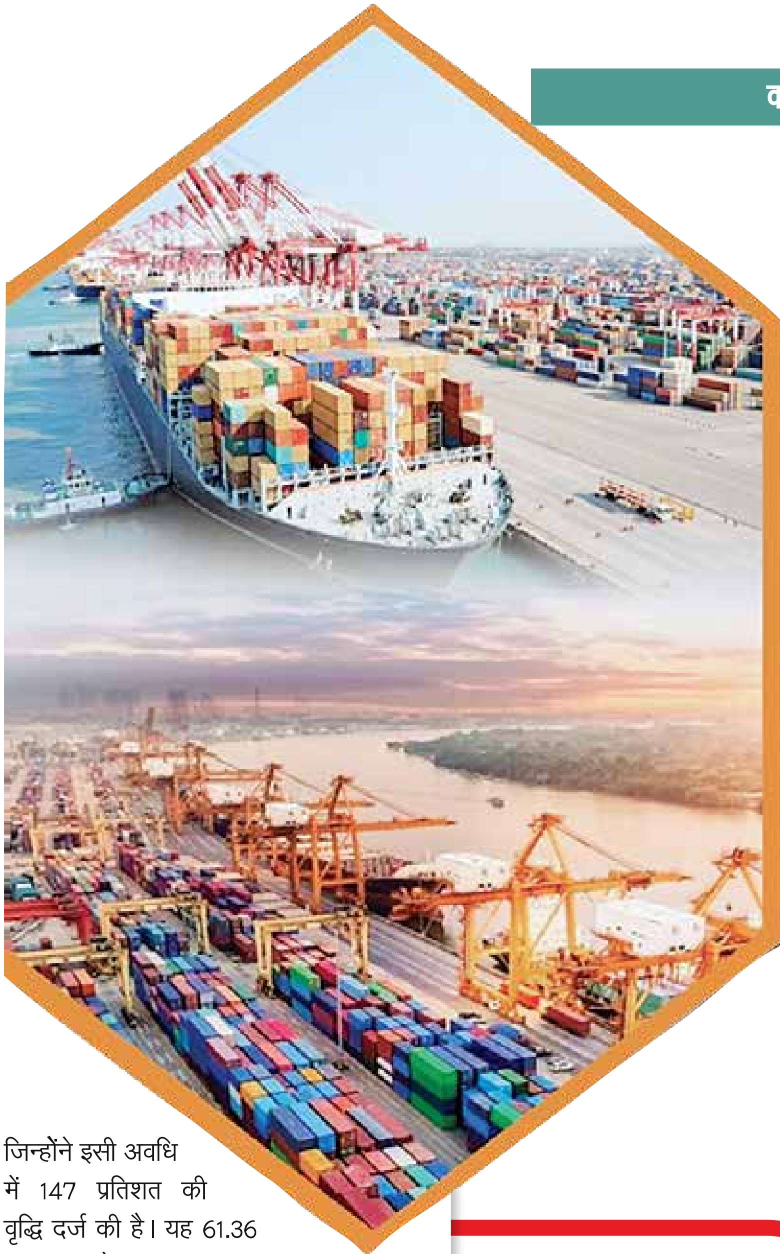

भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में भी दोगुनी वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपये हो गया है। इससे देश की वैश्विक स्तर पर अग्रणी समुद्री खाद्य निर्यातक के रूप में स्थिति और मजबूत हुई है। तटीय मत्स्य पालन, विशेष रूप से झींगा पालन में काफी विस्तार हुआ है। पिछले दशक में झींगा उत्पादन में 296 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 3.22 लाख टन से बढ़कर लगभग 12.76 लाख टन हो गया है। यह वृद्धि इस क्षेत्र में उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। ■

भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में भी दोगुनी वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपये हो गया है। इससे देश की वैश्विक स्तर पर अग्रणी समुद्री खाद्य निर्यातक के रूप में स्थिति और मजबूत हुई है। तटीय मत्स्य पालन, विशेष रूप से झींगा पालन में काफी विस्तार हुआ है।

डेयरी विकास से गांवों में बढ़ेगी समृद्धि

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का बजट रिकॉर्ड 6,153 करोड़ रुपये पर पहुंचा, 27 प्रतिशत की हुई वृद्धि

अब निजी क्षेत्र भी खोल सकेंगे वेटनरी कॉलेज, हॉस्पिटल, टेस्टिंग लैब और पशु प्रजनन केंद्र

युवा सहकार टीम

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पशुपालन क्षेत्र के बजट में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो अब 6,153 करोड़ रुपये हो गया है। यह अब तक का इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा आवंटन है। वित्त वर्ष 2025-26 में पशुपालन क्षेत्र के लिए 4,850 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और पशुधन अर्थव्यवस्था के सतत विकास को सुनिश्चित करने के प्रति यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन क्षेत्रों के लिए बजट में किए गए प्रमुख प्रावधानों में पशुधन मूल्य शृंखला में उत्पादकता, पशु स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों की संपत्ति की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण पशुधन उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रमों, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और रोग निवारण पहलों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है।

वित्त मंत्री ने बजट में बेहतर दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया है। दुग्ध उत्पादन और उससे संबंधित गतिविधियों में लगे सहकारी समितियों और पशुधन किसान उत्पादक संगठनों (एलएफपीओ) को समर्थन देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्वेत क्रांति 2.0 की सफलता के लिए यह बेहद जरूरी है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर एक बनने के बाद भारत का लक्ष्य अब दुग्ध निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य सहकारी कवरेज का विस्तार, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण करना है। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध खरीद में वर्तमान स्तर से 50 प्रतिशत तक वृद्धि करना है, ताकि इनके दायरे में आने वाले क्षेत्रों में डेयरी किसानों को

बाजार तक पहुंच प्रदान की जा सके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके।

पशुपालन क्षेत्र में नवाचार अपनाने, टेक्नोलॉजी के उपयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है। चारा विकास, पशु आहार सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पशुधन प्रथाओं से संबंधित पहल इस क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। पशुपालन और दूध उत्पादन पर अतिरिक्त जोर से रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है।

पशुपालन क्षेत्र के लिए प्रमुख प्रावधान

देश में इस समय पशुधन के मुकाबले पशु चिकित्सा पेशेवरों की काफी कमी है। इससे पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है जिससे दूध उत्पादकता पर असर पड़ता है। अभी इस क्षेत्र में सरकारी संस्थानों का ही दखल है। अब इस क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोलने का प्रस्ताव केंद्रीय बजट में किया गया है। पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाकर 20,000 से अधिक करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के पशु चिकित्सा एवं अर्द्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, पशु अस्पतालों, निदान प्रयोगशालाओं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने किया है। इसके तहत भारतीय एवं विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी आसान बनाया जाएगा।

पशुपालन उद्यम के लिए ऋण-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम: केंद्रीय बजट 2026-27 में पशुपालन में उद्यमिता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋण-आधारित सब्सिडी योजना का प्रस्ताव है, जिससे पशुधन, दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन उद्यमों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक उपकरण अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला विकसित करने में सहायता करना है।

ग्रामीण और संबद्ध कृषि पर व्यापक ध्यान केंद्रित करना : पशुधन, दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन की मूल्य श्रृंखलाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार से उत्पादकता और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म जैसे एआई-आधारित कृषि उपकरण दुग्ध उत्पादन और पशुधन उत्पादकों सहित किसानों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएंगे।

पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने की अन्य पहल: बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इससे डेयरी क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश में नए बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। ■

पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाकर 20,000 से अधिक करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के पशु चिकित्सा एवं अर्द्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, पशु अस्पतालों, निदान प्रयोगशालाओं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने किया है। इसके तहत भारतीय एवं विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी आसान बनाया जाएगा।

मैन्युफैक्चरिंग-एसएमई पर फोकस से बढ़ेगा रोजगार

रोजगारपरक सात मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, रेयर अर्थ, केमिकल, कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल को बढ़ावा देने की घोषणा

सेमीकंडक्टर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की होगी शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का बजट

युवा सहकार टीम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए भले ही यह कहा हो कि यह बजट आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस है मगर उन्होंने इस बजट में सीधे उन्हें कुछ दिए बिना उनके लिए जो प्रावधान किए हैं उसका असर लंबी अवधि में दिखेगा। खासकर मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई (मध्यम, छोटे एवं लघु उद्यम), महिला उद्यमिता और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाने की वित्त मंत्री ने कवायद की है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में युवाओं के रोजगार से संबंधित कई उपाय किए गए थे जिसका इस बार अभाव दिखा।

यह बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है जिनमें विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर को रोजगार सृजन, नवाचार और निर्यात वृद्धि का प्रमुख आधार मानते हुए कदम उठाए हैं। मौजूदा समय में दुनियाभर के देशों में बढ़ते तनाव और टैरिफ वार को देखते हुए घरेलू उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता बन गया है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में 350 से अधिक सुधार लागू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और औद्योगिक विकास को गति देना है।

मैन्युफक्चरिंग को बूस्टर डोज

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सात क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान किए हैं उससे न सिर्फ मेक इन इंडिया की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि निर्यात के मोर्चे पर भी इन क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। रोजगार बढ़ाने वाले इन सात क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, रेयर अर्थ, केमिकल, कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल को शामिल किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से घरेलू स्तर पर वस्तुओं का निर्माण बढ़ेगा जिससे निवेश एवं रोजगार में बढ़ोतरी के साथ आयात में कमी आएगी और निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा। वैश्विक हालात को देखते हुए घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना जरूरी है। इसलिए सात ऐसे सेक्टर का चुनाव किया गया है जो रोजगारपरक हैं। भारत सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा क्षेत्र है जो करोड़ों की संख्या में युवाओं को रोजगार दे सकता है। केंद्र सरकार पहले ही युवाओं को उद्योगों की

जरूरतों के अनुसार कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। ये युवा उत्पादक गतिविधियों से जुड़ कर विकास की प्रक्रिया को तेज करने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

देश को सेमीकंडक्टर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत का ऐलान किया गया है। इससे वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में भारत की स्थित मजबूत होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बजट को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह स्कीम अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई थी जिसे उद्योग जगत की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इसे देखते हुए ही इस स्कीम के लिए बजट में वृद्धि का फैसला किया गया है। यह कदम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की सफलताओं से भी प्रेरित है।

बायोफार्मा हब बनाने की तैयारी

सेमीकंडक्टर की तरह बायोफार्मा क्षेत्र पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि भारत को विश्व का प्रमुख बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाया जा सके। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है। इससे न केवल भारत के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता भी मजबूत होगी। साथ ही उच्च मूल्य वाले उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें।

चिंता बरकरार

हालांकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाने की कवायद सरकार कई सालों से कर रही है लेकिन इसका अपेक्षित नतीजा नहीं निकल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड) स्कीम में छह साल में 1.76 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन चार साल बाद भी इसका सिर्फ 10 -12 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। इसी तरह पिछले साल बजट में पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई थी जिसका मकसद युवाओं को शीर्ष कंपनियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करना है। 2025-26 में इस योजना के लिए 10,831 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था लेकिन अब तक केवल 526 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसे देखते हुए 2026-27 में इस योजना के बजट में बड़ी कटौती करते हुए 4,788 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अगर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ानी है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है रोजगार बढ़ाना। इसके लिए बजट में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो सीधे तौर पर रोजगार सृजन करें। ■

एमएसएमई को 10 हजार करोड़ का पैकेज

वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने पर भी इस बजट में पूरा जोर दिया है। एमएसएमई सेक्टर लंबे समय से संकट से जूझ रहा है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा था जिसे इस बार सरकार ने सुन लिया है। यह क्षेत्र इस बात की मांग करता रहा है कि विनिर्माण इकाइयों के लिए पूंजी की लागत कम की जाए, ताकि उत्पादन और प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ावा मिल सके। यह क्षेत्र न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा योगदान देता है, बल्कि सबसे ज्यादा रोजगार भी इसी क्षेत्र में मिलता है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग में इस क्षेत्र की 35.4 प्रतिशत, निर्यात में 48.58 प्रतिशत और जीडीपी में 31.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। देश में कुल 7.47 करोड़ एमएसएमई हैं जिनमें 35.82 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस क्षेत्र के लिए राहत का उपाय करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि चैंपियन की तरह इन्हें बढ़ाएं। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का प्रावधान किया गया है जिससे छोटे और मझोले उद्यमों को सस्ती वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे उत्पादकों को तो फायदा मिलेगा ही, निर्यातक भी लाभान्वित होंगे। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलने से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 2,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा सक्रिय करने और लघु उद्योगों को मजबूती देने के लिए 7,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, हथकरघा और पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बजट को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह स्कीम अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई थी जिसे उद्योग जगत की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

दिल्ली में बनेगी महिला

विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहकारिता को अर्थव्यवस्था का आधार बनाने का प्रयास पूरे देश में चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इफको, एनसीयूआई, नेफेड, एनसीसीएफ, एनसीडीसी जैसी राष्ट्रीय स्तर की कई सहकारी संस्थाओं का मुख्यालय है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक नहीं है। लंबे समय बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदेश के सहकारिता मंत्री **रविंद्र इंद्राज सिंह** स्थानीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रयास में जुटे हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इस संबंध में उनसे **एसपी सिंह** और **अभिषेक राजा** ने लंबी बातचीत की। पेश हैं उनके प्रमुख अंशः

पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए व्यापक पहल की जा रही है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए क्या-क्या कदम उठाएं हैं या उठा रही है?

आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के विजन 'सहकार से समृद्धि' उत्सव को मना रहा है जिसमें समाज के हर वर्ग का समावेशन हो रहा है। दिल्ली प्रदेश की बात करें तो यहां 6,000 से अधिक कोऑपरेटिव सोसायटी हैं जिसमें लगभग 25 लाख से अधिक लोग एक-दूसरे से जुड़े हैं। हमने दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, चाहे वह हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी हो, थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसायटी हो, सहकारी बैंक हो, हैंडलूम और

कोऑपरेटिव सोसायटी

हैंडीक्राफ्ट, मल्टीपरपस कोऑपरेटिव सोसायटी और अन्य जितनी भी अन्य कॉपरेटिव सोसायटीज हैं, उन सबको एक समान मंच देने का काम किया है और कर रहे हैं। हम उनके रिडेवलपमेंट और रिफॉर्म के साथ अन्य प्रदेशों द्वारा लागू सफल सहकारिता मॉडल का भी अध्ययन कर उन्हें दिल्ली में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे दिल्ली में आवासीय, वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पुरानी हाउसिंग सोसायटी को लेकर लगातार रिडेवलपमेंट नीतियों पर चर्चा हो रही है। साथ ही नए सेक्टर जैसे पर्यटन, इंश्योरेंस, हरित उर्जा, टैक्सी, परिवहन आदि पर हम लगातार काम कर रहे हैं।

हमने अभी हाल ही में डीसीएचएफसी जो हमारा बहुत बड़ा कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, की नई ब्रांच का रोहिणी के सेक्टर 15 में उद्घाटन किया है। यह प्राइवेट बैंक को कड़ी टक्कर दे रहा है। यह बहुत कम ब्याज 7.4 प्रतिशत तक पर हाउसिंग लोन दे रहा है। दिल्ली में 15 सहकारी बैंक हैं जिनकी 145 शाखाएं हैं। हम जल्द ही कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ेगा और कोऑपरेटिव के हितों की रक्षा करेगा।

दिल्ली में थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसायटी की व्यापक मौजूदगी है। इसके बावजूद कर्ज का प्रवाह बहुत कम है। इसकी क्या वजह है और इस चुनौती से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

दिल्ली में इस समय 1,600 से ज्यादा थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसायटीज हैं। हमने इसमें तरह-तरह की थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसायटी के फेडरेशन को एक समान मंच देने का काम किया जिससे कर्जदाता और लेनदार के बीच एक सामंजस्य स्थापित हुआ है। कर्ज के प्रवाह को बढ़ाने के लिए हम प्रक्रियाओं को सरल, समयबद्ध और सहकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हम डि-सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहे हैं। कर्जदाता की परेशानियों को कम करने के लिए तीन रिकवरी ऑफिसर यानी सहायक कलेक्टर बना रहे हैं ताकि पारदर्शिता के साथ-साथ रिकवरी प्रक्रिया में सुधार हो सके। साथ ही कर्ज लेने वालों के लिए ब्याज पर ब्याज की व्यवस्था को संशोधित करके मूलधन पर ही ब्याज की व्यवस्था को लागू करेंगे। पैनल इंटरेस्ट को भी हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे प्रावधानों में भी संशोधन करने वाले हैं जो अभी लोगों के हित में नहीं हैं। उन पर लगातार कोऑपरेटिव के जानकारों से विचार-विमर्श कर रहे हैं और एक संशोधन बोर्ड का भी गठन कर रहे हैं।

युवाओं और महिलाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है?

महिलाएं परिवार और समाज दोनों को सशक्त करने में सक्षम हैं। सहकारी समितियों के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण के लिए एक ऐसी नई कोऑपरेटिव सोसायटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसकी सदस्य सिर्फ महिलाएं होंगी और महिलाएं हीं उनका संचालन करेंगी। स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं को लगातार कोऑपरेटिव से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो महिला घर पर रहकर ही काम कर सकती है और जो घर में ही विभिन्न प्रोडक्ट्स का निर्माण करती हैं जैसे- अगरबत्ती, दीया, पापड़, सेव, बड़ी, जवै, खूशबूदार सामान आदि, हम ऐसी महिलाओं को कोऑपरेटिव का मंच देकर उनके जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक युवाओं की बात है तो उन्हें जागरूक करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन कर उन्हें सहकारिता से जोड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है।

दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों की बहुत बड़ी संख्या है। उन्हें कोऑपरेटिव से जोड़कर सस्ता लोन उपलब्ध कराने की बात आपने कही थी। क्या वह योजना बन चुकी है? उसकी क्या स्थिति है?

उस पर लगातार काम चल रहा है। इसके लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सहकारी बैंकों से उन्हें सस्ता कर्ज दिलाने के लिए हम ऐसा मॉडल तैयार करने पर काम कर रहे हैं जिसमें मोबाइल एटीएम वैन के जरिये उनके घर के पास ही उन्हें कर्ज उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली के बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा और ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देकर उनके लिए नई कोऑपरेटिव बनाई जाएगी। इनके माध्यम से लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर उनके सामान की बिक्री का एक माध्यम बनाया जाएगा। इसके लिए कोऑपरेटिव स्टोर खोलने के अलावा एक पोर्टल विकसित किया जाएगा जहां वे अपने सामान को बेच सकेंगे। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में ऐसा ही एक स्टोर खोलने की तैयारी हो चुकी है। ■

तीन साल में देशभर में दौड़ने लगेगी भारत टैक्सी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता आधारित देश की पहली टैक्सी सेवा की औपचारिक शुरुआत की

दिल्ली-एनसीआर में 2.5 लाख से ज्यादा सारथी और 8.5 लाख से ज्यादा यात्री इस टैक्सी सेवा से जुड़े

युवा सहकार टीम

सहकारिता के माध्यम से परिवहन क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए भारत टैक्सी की औपचारिक शुरुआत हो गई। अभी इसकी शुरुआत दिल्ली-एनसीआर और गुजरात के राजकोट में हुई है। अगले तीन साल में देश के हर बड़े शहरों में भारत टैक्सी की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इससे न सिर्फ निजी टैक्सी सेवा कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगेगी, बल्कि यात्रियों और ड्राइवरों दोनों को फायदा मिलेगा। यात्रियों को जहां व्यस्त समय में निजी कंपनियों के बढ़ते किराये से मुक्ति मिलेगी क्योंकि इसका किराया हर समय एक समान रहेगा, वहीं ड्राइवरों को बिना कमीशन दिए पूरा किराया मिलेगा। साथ ही भारत टैक्सी का संचालन करने वाली कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के भी वह सदस्य होंगे और उनके पास इसका मालिकाना हक होगा। यानी यह ड्राइवरों के स्वामित्व वाली टैक्सी सेवा है। इस कोऑपरेटिव के मुनाफे में से 20 प्रतिशत लाभांश ड्राइवरों को मिलेगा। भारत टैक्सी के पुरुष ड्राइवरों को सारथी और महिला ड्राइवरों को सारथी दीदी के नाम से जाना जाएगा। ऐप आधारित इस टैक्सी सेवा में चार पहिया, तीन

पहिया और दो पहिया वाहन यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं।

हालांकि, पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने के बाद 1 जनवरी, 2026 से ही दिल्ली-एनसीआर और गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और द्वारका में भारत टैक्सी का संचालन शुरू हो गया था मगर इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी को नई दिल्ली में इसका औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीयय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर एवं मुरलीधर मोहोल और सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित 1,200 से अधिक सारथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक का एक मॉडल तैयार कर रहा है। तीन साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामख्या तक भारत टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगी। जब पहली बार मैंने संसद के सामने सहकार टैक्सी का विषय रखा तो बहुत सारे लोगों, खासकर टैक्सी परिचालन से जुड़ी कंपनियों ने सवाल उठाया कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में क्यों प्रवेश कर रही है। ऐसे लोगों को 'सहकार' और 'सरकार' के बीच का भेद नहीं मालूम है। सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही, बल्कि सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।'

पूरी दुनिया में पहली बार सहकार आधारित ऐसी टैक्सी कंपनी अस्तित्व में आई है, जिसका असली मालिक कोई व्यक्ति या बाहरी कंपनी नहीं, बल्कि टैक्सी चलाने वाले लोग हैं। भारत टैक्सी एक ड्राइवर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जहां ड्राइवर ही इसके सह-मालिक हैं। इसका मकसद ड्राइवरों को शोषण से बचाना और उन्हें कमाई का पूरा हक देना है। यह संकल्पना सहकार टैक्सी से जुड़ने वाले सारथियों के जीवन, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाली है। दिल्ली-एनसीआर में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सारथी और 15 लाख से ज्यादा यात्री इससे जुड़ चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि अब टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई के लिए नहीं, बल्कि टैक्सी सारथियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए घूमेगा। इस कोऑपरेटिव के प्रमोटरों में अमूल, इफको, कृभको, नेफेड, एनडीडीबी, एनसीईएल, एनसीडीसी और नाबार्ड जैसी संस्थाएं शामिल हैं। अमूल के एमडी जयेन मेहता इसके चेयरमैन हैं।

100 रुपये में सारथी बनेंगे मालिक

भारत टैक्सी से जुड़ने वाले सारथी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड का न्यूनतम एक और अधिकतम पांच शेयर ले सकेंगे। इसका मूल्य प्रति शेयर 100 रुपये रखा गया है। अगर सारथी अधिकतम शेयर भी लेते हैं तो 500 रुपये में ही वह इस कोऑपरेटिव के सदस्य बनकर मालिकाना हक हासिल कर

- **भारत टैक्सी की 'सारथी दीदी' की सुविधा महिलाओं को सुरक्षा और सारथी दीदियों को सम्मान व आत्मनिर्भरता देगी**
- **इसके चार मूल विचार हैं - स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान और लाभांश का समान वितरण**
- **इसके आते ही कई बड़ी कंपनियों ने अपने कमीशन कम कर ड्राइवरों और यात्रियों को डिस्काउंट देना किया शुरू**
- **सारथियों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, बीमा, सस्ते लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा**
- **भारत टैक्सी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो, एएआई, एसबीआई सहित 9 प्रमुख संस्थानों के साथ हुआ एमओयू**

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत टैक्सी से जुड़ने वाले सारथियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सारथी दीदी की एक खास संकल्पना तैयार की गई है जिसके तहत आने वाले समय में ऐप में सारथी दीदी के लिए एक अलग विंडो होगी। इसके जरिये रजिस्ट्रेशन कराने वाली किसी भी महिला को केवल सारथी दीदी ही पिक करने आएंगी। सारथी दीदी बाइक लेकर आएंगी और बहुत कम किराए में सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाएंगी।

लेंगे। यह छोटी सी राशि टैक्सी सारथियों की मेहनत, आत्मसम्मान और उनकी आर्थिक आजादी की नींव बनने जा रही है। हर पांच साल पर इस कोऑपरेटिव का चुनाव होगा जिसमें डेलिगेट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाएंगे। चुनाव के बाद टैक्सी सारथियों द्वारा चुने गए दो डायरेक्टर्स बोर्ड में रखे जाएंगे जो उनके हितों की देखभाल करेंगे और उनके लिए फैसले करेंगे।

सारथी दीदी की विशेष सुविधा

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत टैक्सी से जुड़ने वाले सारथियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सारथी दीदी की एक खास संकल्पना तैयार की गई है जिसके तहत आने वाले समय में ऐप में सारथी दीदी के लिए एक अलग विंडो होगी। इसके जरिये रजिस्ट्रेशन कराने वाली किसी भी महिला को केवल सारथी दीदी ही पिक करने आएंगी। सारथी दीदी बाइक लेकर आएंगी और बहुत कम किराए में सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाएंगी। यह सुविधा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी और व्यावहारिक राहत साबित होगी। यह सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नौ प्रमुख संस्थाओं से एमओयू

भारत टैक्सी ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इफको टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कुल नौ प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता किया है। इन समझौतों के जरिये यात्रियों को कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी और इन सभी संस्थाओं को भारत टैक्सी की सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। आने वाले दिनों में सारथियों को इंश्योरेंस, सरकारी रोजगार योजनाओं, लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ स्वतः मिल सकेगा। ताकि हर सारथी को पूरा सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिल सके। केंद्र सरकार ने सवा करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स के लिए कई सारी योजनाओं और सुविधाओं की शुरुआत की है। पहले ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार केवल उन लोगों को था जिनकी पेंशन कटती थी या जो औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त श्रमिक के रूप में पंजीकृत थे। अब इस सीमा को हटा दिया गया है। भारत टैक्सी से जुड़े सभी सारथी अब आसानी से ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें और उनके परिवार वालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध अन्य कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी उनके लिए अपने आप सक्रिय हो जाएंगी।

सारथियों को तुरंत होगा भुगतान

भारत टैक्सी सारथियों से कमीशन नहीं लेगी जिससे उन्हें पूरा किराया मिलेगा। इसका उद्देश्य कंपनी की पूंजी को बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत टैक्सी के असली मालिक सारथी भाइयों और सारथी दीदियों की आमदनी बढ़ाना है। यात्रियों द्वारा किया गया भुगतान सीधे सारथी के अकाउंट में तत्काल ऑटोमैटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों की टैक्सी सेवा में यात्रियों द्वारा किया गया किराया भुगतान पहले कंपनी के अकाउंट में जाता है, फिर कंपनियां अपना कमीशन काटकर ड्राइवरों को भुगतान करती हैं। किसी भी सारथी का अकाउंट बिना उचित सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा। यात्रियों की ओर से सारथियों के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों की सुनवाई के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष सुनवाई के बाद ही सारथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी।

नए-नए क्षेत्रों में लागू होगा सहकारी मॉडल

अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की शुरुआत सहकारिता क्षेत्र के लिए नए आयाम खोलने की भी शुरुआत है। पिछले 125 वर्षों से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि सहकारी मॉडल को नए-नए क्षेत्रों में ले जाया जाए। सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक वाला मॉडल तैयार कर रहा है। आने वाले समय में तीन-चार ऐसे क्षेत्रों में इस मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा जहां मेहनत करने वाले व्यक्ति के पसीने और परिश्रम का फल उसी के पास रहेगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी के चार मूल मंत्र हैं-स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान और सबका पहिया, सबकी प्रगति यानी सभी के लिए लाभांश का उचित वितरण। इन्हीं चार उद्देश्यों के साथ भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है।

सुरक्षा का खास ख्याल

भारत टैक्सी के ऐप में एसओएस अलर्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से आपातकालीन स्थिति में तुरंत सुरक्षा और सहायता प्राप्त की जा सकती है। अभी दिल्ली-एनसीआर में आठ हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। आने वाले समय में देशभर में ऐसे केंद्रों का व्यापक जाल बिछाया जाएगा। शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया तीन स्तरों पर संचालित होगी। ऐप के माध्यम से, वेबसाइट पर और टोल-फ्री नंबर के जरिये। इसके साथ ही सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के प्रतिनिधि नियमित रूप से सारथियों के साथ बैठकें करेंगे ताकि हर समस्या का समय पर समाधान हो सके। साथ ही 24 घंटे, सातों दिन सारथियों के लिए हेल्पलाइन की सेवा उपलब्ध रहेगी। आने वाले दिनों में भारत टैक्सी में बहुत सारी नई सेवाओं को शामिल किया जाएगा। ■

भारत टैक्सी सारथियों से कमीशन नहीं लेगी जिससे उन्हें पूरा किराया मिलेगा। इसका उद्देश्य कंपनी की पूंजी को बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत टैक्सी के असली मालिक सारथी भाइयों और सारथी दीदियों की आमदनी बढ़ाना है। यात्रियों द्वारा किया गया भुगतान सीधे सारथी के अकाउंट में तत्काल ऑटोमैटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों की टैक्सी सेवा में यात्रियों द्वारा किया गया किराया भुगतान पहले कंपनी के अकाउंट में जाता है, फिर कंपनियां अपना कमीशन काटकर ड्राइवरों को भुगतान करती हैं।

स्टार्टअप इंडिया का एक दशक

भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब, 2 लाख से अधिक हुए स्टार्टअप्स जिनमें 125 यूनिकॉर्न

वर्ष 2025 में लगभग 44,000 नए स्टार्टअप हुए रजिस्टर्ड, किसी भी एक वर्ष में सबसे बड़ी वृद्धि

स्टार्टअप्स में 20 लाख से अधिक लोगों को मिला हुआ है प्रत्यक्ष रोजगार

स्टार्टअप्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का समयः प्रधानमंत्री

युवा सहकार टीम

नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने और निवेश संचालित विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक दशक पहले 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना, टैक्स प्रोत्साहन, आसान नियम और आसन वित्तपोषण के माध्यम से भारत को 'नौकरी मांगने वालों' की बजाय 'नौकरी देने वाला' देश बनाना है। पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत की आर्थिक और नवाचार संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। इसने संस्थागत प्रणालियों को मजबूत किया है, पूंजी और मार्गदर्शन तक पहुंच का विस्तार किया है और स्टार्टअप्स को विभिन्न क्षेत्रों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में विकास और विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। इसकी वजह से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं जिनमें से 125 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न की श्रेणी वह स्टार्टअप आते हैं जिनकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से अधिक होती है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करने, नवाचार आधारित आर्थिक विकास और विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

16 जनवरी को अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा, 'इस वर्ष का उत्सव विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के एक दशक पूरा होने का प्रतीक है। यह दिन लोगों, विशेषकर युवाओं के साहस, नवाचार की भावना और उद्यमशीलता के उत्साह का महोत्सव मनाने का दिन है, जिन्होंने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत के उत्थान को गति प्रदान की है। स्टार्टअप्स परिवर्तन के ऐसे इंजन हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ये हमारी धरती की चुनौतियों का समाधान करने और साथ ही लोगों के लिए अवसरों

का सृजन करने में असाधारण कार्य कर रहे हैं। मुझे उन सभी लोगों पर गर्व है जिन्होंने बड़े सपने देखने का साहस किया, पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी, जोखिम उठाए और अपने स्टार्टअप्स के माध्यम से परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न किया। भारत सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत द्वारा शुरू की गई सुधार पहल ने स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। हमारे स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।'

गांवों में खुल रहे स्टार्टअप

पहले नए व्यवसाय और उद्यम मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक परिवारों के बच्चों द्वारा शुरू किए जाते थे, क्योंकि केवल उन्हीं को आसानी से वित्तपोषण और समर्थन प्राप्त होता था। मध्यम वर्ग और गरीबों के बच्चे केवल रोजगार का ही सपना देख सकते थे। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने इस मानसिकता को बदल दिया है। अब बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों और यहां तक कि गांवों के युवा भी स्टार्टअप खोल रहे हैं और जमीनी स्तर की सबसे गंभीर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिवर्तन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 45 प्रतिशत से अधिक में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या भागीदार हैं। भारत महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप फंडिंग में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है।

दो लाख स्टार्टअप, 20 लाख रोजगार

स्टार्टअप इंडिया के दस साल पूरे हो गए हैं। यह सफर सिर्फ एक सरकारी योजना की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों सपनों और अनगिनत कल्पनाओं के साकार होने की गाथा है। दस साल पहले व्यक्तिगत प्रयासों और नवाचार के लिए बहुत कम गुंजाइश थी, लेकिन स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को असीमित अवसर दिए और आज इसके परिणाम देश के सामने हैं। महज 10 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक क्रांति बन गया है। दस साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। 2014 में भारत में केवल चार यूनिकॉर्न थे, जबकि आज लगभग 125 सक्रिय यूनिकॉर्न हैं। अकेले वर्ष 2025 में लगभग 44,000 नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए, जो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद से किसी भी एक वर्ष में सबसे बड़ी वृद्धि है। भारत के स्टार्टअप रोजगार, नवाचार और विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में आज 20 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है।

सरकार ने खोला खजाना

स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है, जबकि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इन-स्पेस सीड फंड और निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम जैसी योजनाएं स्टार्टअप्स को शुरुआती वित्तपोषण प्रदान कर रही हैं। कर्ज तक पहुंच में सुधार के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। इसी तरह शोध को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना शुरू की गई है। साथ ही उभरते क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश का समर्थन करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडप में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की महत्वाकांक्षा केवल भागीदारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैश्विक नेतृत्व हासिल करने का लक्ष्य होना चाहिए और अब स्टार्टअप उद्यमों के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। ■

स्टार्टअप्स परिवर्तन के ऐसे इंजन हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ये हमारी धरती की चुनौतियों का समाधान करने और साथ ही लोगों के लिए अवसरों का सृजन करने में असाधारण कार्य कर रहे हैं। मुझे उन सभी लोगों पर गर्व है जिन्होंने बड़े सपने देखने का साहस किया, पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी, जोखिम उठाए और अपने स्टार्टअप्स के माध्यम से परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न किया।

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

एनवाईसीएस का विशेष सेवा अभियान

मकर संक्रांति के अवसर पर एनवाईसीएस की चंडीगढ़ शाखा ने जरूरतमंदों में वितरित किए कंबल

युवा सहकार टीम

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) की चंडीगढ़ शाखा ने एक विशेष सेवा अभियान का आयोजन किया। यह न केवल एक सामाजिक पहल थी, बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प का भी प्रतीक बनी। इस अभियान का नेतृत्व संस्था के निदेशक देविंदर सिंह ने किया। उनकी प्रेरणा, दूरदृष्टि और मानवीय संवेदना ने इस प्रयास को एक नई ऊंचाई दी।

जनवरी में मोहाली क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को प्रभावित किया हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, जिनके पास सर्दियों के पर्याप्त वस्त्र नहीं होते, जिनके घरों में गर्माहट का कोई साधन नहीं होता, उनके लिए यह मौसम केवल ठंड नहीं, बल्कि एक संघर्ष बन जाता है। ऐसे समय में एनवाईसीएस की टीम ने यह संकल्प लिया कि वे केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सक्रिय सहायता प्रदान करेंगे। टीम के सदस्यों ने मोहाली के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद परिवारों की पहचान की और उन्हें कंबल वितरित किए। यह वितरण केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक मानवीय संवाद था जहां हर कंबल के साथ एक मुस्कान, एक स्नेहिल स्पर्श और एक आश्वासन भी दिया गया कि आप अकेले नहीं हैं।

कंबल नहीं, करुणा की चादर

जब हम किसी को कंबल देते हैं, तो वह केवल एक वस्त्र नहीं होता। वह एक संदेश होता है सुरक्षा का, अपनत्व का और सामाजिक एकता का। एनवाईसीएस द्वारा वितरित किए गए ये कंबल उन परिवारों के लिए सर्दी से राहत का साधन तो बने ही, साथ ही यह भी दर्शाया कि समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। हर कंबल के साथ एक कहानी

जुड़ी थी। किसी बुजुर्ग की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, किसी मां की मुस्कान थी जो अपने बच्चे को गर्माहट में लिपटा देख रही थी, किसी युवा की आशा जो पहली बार महसूस कर रहा था कि समाज उसे देख रहा है, समझ रहा है।

सेवा एक सतत संकल्प

यह सेवा अभियान यह भी सिखाता है कि सेवा एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि यह एक जीवन मूल्य है। यह वह भावना है जो हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाती है। सेवा वह दीप है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। यह वह पुल है जो समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ता है। यह वह भावना है जो संवेदनशीलता, करुणा और समावेशिता को जीवंत करती है। एनवाईसीएस का यह प्रयास इस बात का प्रमाण है कि जब संगठन और व्यक्ति मिलकर समाज के लिए कार्य करते हैं, तो परिवर्तन संभव होता है।

नेतृत्व जो प्रेरणा बन जाए

इस अभियान की सफलता का श्रेय देविंदर सिंह को जाता है जिनका नेतृत्व केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि मानवीय और प्रेरणादायक भी है। उन्होंने न केवल योजना बनाई, बल्कि स्वयं मैदान में उतरकर टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। उनका यह व्यवहार दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सेवा में सबसे आगे हो। उनकी प्रेरणा से एनवाईसीएस की टीम ने न केवल कंबल वितरित किए, बल्कि सेवा के बीज भी बोए जो आने वाले समय में और भी सामाजिक पहलों के रूप में फलित होंगे।

मकर संक्रांति केवल तिल और गुड़ का पर्व नहीं है, यह सामाजिक समरसता, आत्मिक उन्नयन और सेवा के संकल्प का पर्व है। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकाश केवल दीपक से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से भी फैलता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो हम केवल उसका जीवन नहीं संवारते, बल्कि अपने भीतर भी एक नई रोशनी का संचार करते हैं।

आगे की राह

यह सेवा अभियान एक शुरुआत है। एनवाईसीएस की चंडीगढ़ शाखा का उद्देश्य है कि हर पर्व, हर अवसर को सेवा के माध्यम से सार्थक बनाया जाए। आने वाले समय में यह सहकारी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्र में भी सेवा कार्य करेगी। युवाओं को सेवा कार्यों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण और प्रेरणा सत्र आयोजित करेगी। समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए स्थानीय संगठनों और प्रशासन के साथ समन्वय करेगी। एनवाईसीएस का यह सेवा अभियान इस बात का प्रमाण है कि पर्व केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि समाज के प्रति दायित्व निभाने का भी माध्यम हो सकते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यह संकल्प लिया गया कि सेवा, सहयोग और करुणा को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और करुणा से सुंदर कोई उत्सव नहीं। ■

इस अभियान की सफलता का श्रेय देविंदर सिंह को जाता है जिनका नेतृत्व केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि मानवीय और प्रेरणादायक भी है। उन्होंने न केवल योजना बनाई, बल्कि स्वयं मैदान में उतरकर टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। उनका यह व्यवहार दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सेवा में सबसे आगे हो।

भविष्य के सितारे

वैभव, आयुष और विहान

बहुत जल्द भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के लिए खेलते दिख सकते हैं **वैभव सूर्यवंशी**

सत्येन्द्र पाल सिंह

चौदह बरस के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से और उपकप्तान विहान मल्होत्रा, कप्तान आयुष म्हात्रे, कनिष्क चौहान एवं आरएस अंबरीश ने बल्ले के साथ गेंद से भी दमदार प्रदर्शन कर भारत को छठी बार आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जिता कर दिखा दिया कि वे भविष्य के सितारे हैं। वैभव सूर्यवंशी की 175 रन की तूफानी पारी से भारत ने इंग्लैंड को हराने में हुए फाइनल में 100 रन से हरा कर 'खिताबी' छक्का जड़ा। मोहम्मद कैफ (2000), विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2012) , पृथ्वी शॉ (2018) , यश धुल (2022) के बाद आयुष म्हात्रे (2026) भारत को अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले छठे कप्तान कप्तान बन गए हैं। भारत ने फाइनल सहित सभी सात मैच जीत खिताब जीता।

इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स), आयुष म्हात्रे (चेन्नई सुपर किंग्स) और विहान मल्होत्रा (आरसीबी) धमाल कर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस साल खेलते दिख सकते हैं। पिछली आईपीएल में अपने बल्ले का कमाल दिखा चुके सूर्यवंशी और म्हात्रे जरूर भारत की टी20 टीम में स्थान बनाने का दावा पेश करते नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2016 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नियम के तहत कोई भी खिलाड़ी केवल एक अंडर-19 विश्व कप ही खेल सकता है। मात्र 14 बरस के वैभव सूर्यवंशी सहित भारत के कल के ये सभी सितारे अब कोई और अंडर-19 विश्व कप नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई का मकसद ज्यादा से ज्यादा जूनियर खिलाड़ियों को अंडर-19 विश्व कप में खेलने का मौका देकर जूनियर खिलाड़ियों का बड़ा पूल बनाना था। इस नियम का एक फायदा यह हुआ कि जूनियर खिलाड़ियों की उम्र में गड़बड़ी कर अंडर-19 विश्व कप में खेलने का मसला खत्म हो गया। इससे सही में अंडर-19 क्रिकेटर ही शिरकत कर पाए।

> “अंडर-19 विश्व कप खिताब जीतने पर मैं अपने अहसास को बयां नहीं कर सकता। बीते सात-आठ महीने से टीम में हम सभी लड़के और हमारे सपोर्ट स्टाफ ने यह पक्का किया कि हम सभी पूरी तरह फिट रहें। हमने दबाव नहीं लिया और अपना नैसर्गिक खेल खेलते रहे। मुझे अपने कौशल पर भरोसा था कि मैं फाइनल जैसे बड़े मैच में योगदान कर सकता हूं।
>
> **– वैभव सूर्यवंशी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट**

> “भारत का अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतना शानदार अहसास है। खिताब जीतने वाली टीम के ये लड़के शानदार हैं। फाइनल में इग्लैंड के संघर्ष के बाद हमारी टीम की यह खिताबी जीत वाकई गजब की है। हम अपनी टीम के लड़कों की तरक्की देख कर बहुत खुश हैं। बेशक हम ट्रॉफियों के लिए खेलते हैं लेकिन हमारे ये नौजवान जिस तरह बतौर क्रिकेटर परिपक्व हुए, वह सुखद है।
>
> **– ऋषिकेश कानितकर, अंडर-19 टीम के चीफ कोच**

> “मेरे लिए यह बेहद यादगार क्षण है। हमारे लड़कों ने फाइनल सहित पूरे विश्व कप में शानदार खेल दिखाया। हमने अपनी योजना को अमली जामा पहना कर अंडर-19 विश्व कप जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल किया। मैं खुश हूं कि हमारे लड़कों ने अपना नैसर्गिक खेल दिखाया। वैभव सूर्यवंशी की फाइनल में 175 रन की यादगार पारी को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि वैभव कितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उन्होंने फाइनल में दिखाया कि वह क्या कर सकते हैं।
>
> **– आयुष म्हात्रे, अंडर-19 टीम के कप्तान**

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 विश्व कप में तीन अर्द्धशतकों और फाइनल में मात्र 80 गेंदों में 15 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 175 रन की मदद से कुल सात मैचों में एक शतक सहित 439 रन बना कर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाने के बाद उन्हें सचिन तेंडुलकर की तरह किशोर क्रिकेटर के रूप में भारत की सीनियर टीम में शामिल किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सचिन तेंडुलकर ने 1989 में मात्र 16 बरस की उम्र में कृष्णमाचारी श्रीकांत की कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में पहले टेस्ट से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर ने एक वर्ग के विरोध के बावजूद उन्हें 16 बरस की उम्र में भारत के लिए टेस्ट खेलने का मौका दिया। इसके बाद तो वह करीब दो दशक तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छाए रहे। उसी तरह बीसीसीआई का एक धड़ा इस समय वैभव को भारत की सीनियर टीम में जल्दी शामिल करने के पक्ष में है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने किसी भी देश की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए खेलने की न्यूनतम उम्र 15 बरस तय की है। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर में 27 मार्च, 2011 को जन्में वैभव को इस नियम के तहत भारत की सीनियर टीम में खेलने के लिए 27 मार्च, 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष मिथुन मनहास और सचिव देवजीत साइकिया की जोड़ी आने वाले कल में नया इतिहास रचने की संभावना दिखाने वाले वैभव को इग्लैंड में उसके खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों और तीन वन डे अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में सीनियर टीम में खेलने का मौका देगी।

आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 की खिताबी जीत ने यह साबित किया कि किसी एक या दो क्रिकेटरों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत फाइनल तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन चैंपियन नहीं बना जा सकता है। 2026 के संस्करण में सबसे ज्यादा रन इग्लैंड के बेन मेज (7 मैच में एक शतक एवं दो अर्द्धशतक सहित कुल 444 रन) ने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट तेज गेंदबाज लुम्सडेन (7 मैच में 16 विकेट) ने चटकाए। अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने के बावजूद वे खिताब नहीं जिता सके। भारतीय टीम की खुशकिस्मती यह रही कि उसे हर झटके से उबारने के लिए कोई एक आगे आते रहे और मझधार में पड़ी नैया किनारे लगाने में सफल रहे। इसी से भारत चैंपियन बना।

वैभव सूर्यवंशी (कुल 439 रन) ने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ, एरोन जॉर्ज ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ और उपकप्तान विहान मल्होत्रा (7 मैच में कुल 240) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक जड़ अंडर-19 विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। वहीं गेंदबाजों में भारत के लिए तेज गेंदबाज हेनिल पटेल और आरएस अंबरीश समान रूप से सात-सात मैचों में 11-11 विकेट चटका क्रमशः आठवें और नौवें नंबर रहे। विहान मल्होत्रा ने एक शतक सहित 240 रन बनाने के साथ पांच विकेट, कप्तान आयुष म्हात्रे ने तीन अर्द्धशतकों सहित 214 रन बनाने के साथ सात विकेट, अभिज्ञान कुंडु ने बेहतरीन विकेटकीपिंग के साथ अहम वक्त पर दो अर्द्धशतक सहित 239 रन बनाए। ■

उत्तराखंड की सहकारी समितियां सुरक्षा बलों को मुहैया करा रहीं रसद व डेयरी उत्पाद

युवा सहकार टीम

केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही देश भर में सहकारी क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। सहकारी क्षेत्र में हुए 100 से अधिक महत्वपूर्ण सुधारों ने सहकारी समितियों को अधिक सक्षम और बहुउपयोगी बनाया है, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों के बहुआयामी विकास का माध्यम बन रहीं हैं। उत्तराखंड देश में हो रहे सहकारी विकास में एक अग्रणी स्थान बना रहा है, जहां सहकारी प्रणाली को अंतिम छोर तक समावेशन और प्रथम छोर तक एकत्रीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य की सहकारी समितियां सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा कर रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) जैसे सुरक्षा बलों को रसद सामग्री और डेयरी एवं पोल्ट्री उत्पादों की सप्लाई कर रही हैं।

सीमावर्ती जिलों के किसानों और पशुपालकों से पशुधन और पशु मांस की आपूर्ति के लिए उत्तराखंड सहकारी संघ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के बीच एक समझौता हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय उत्पादों, भेड़, बकरी, मुर्गी, ट्राउट मछली, दूध, पनीर और ताजी सब्जियों की आपूर्ति के लिए आईटीबीपी से यह समझौता वाइब्रेट विलेज योजना के तहत किया है। इसके तहत आईटीबीपी को स्थानीय सहकारी समितियों और एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के माध्यम से ताजे और जैविक उत्पाद मिल रहे हैं। यह पहल चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के सीमावर्ती गांवों के किसानों को रोजगार देकर सीधे 11,000 से अधिक पशुपालकों जिनमें 7,000 महिलाएं हैं, को लाभान्वित कर रही है। इन किसानों का भुगतान भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 24-48 घंटे के भीतर हो जाता है। राज्य सरकार ने इसके लिए ब्याज रहित लोन के रूप में पांच करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड भी बनाया है।

उत्तराखंड के पहाड़ी और सीमांत इलाकों से पलायन एक बड़ी समस्या है। इस पहल से सीमांत गांवों से पलायन रोकने और 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इस साल सीमांत गांवों के पशुपालक-किसानों से 32.76 करोड़ रुपये के उत्पाद खरीदे जाएंगे। आईटीबीपी के अधिकारियों ने स्थानीय उत्पादों की प्रस्तावित खरीद का ब्योरा सरकार को दे दिया है। इस वर्ष पशुपालकों और किसानों से जीवित भेड़ बकरी, मुर्गे, ट्राउट मछली के साथ ही पनीर, ताजा दूध, सब्जियां खरीदी जाएंगी। खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आईटीबीपी की 14 से अधिक बटालियनों को राज्य के सीमांत गांवों से खाद्य सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति हो रही है। यह पहल नवंबर 2024 में शुरू हुई थी। इस पहल से राज्य के पशुपालकों, मत्स्य पालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। साथ ही स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहायता मिल रही है। इस व्यवस्था से बिचौलिये खत्म हो गए हैं और सीमावर्ती किसानों को एक निश्चित बाजार मिल गया है।

सेना तक रसद आपूर्ति का उत्कृष्ट सहकारी मॉडल

राज्य के सीमांत गांवों की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), जिला मार्केटिंग समितियों और एक शीर्ष महासंघ ने मिलकर खेत से सेना तक रसद आपूर्ति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो ताजा खाद्य उपज और आवश्यक वस्तुओं को विश्वसनीयता, गुणवत्ता और शीघ्रता के साथ सुरक्षा बलों तक पहुंचाता है। इसे अब राज्य के सभी 13 जिलों में 26 क्लस्टर के जरिए लागू किया जा रहा है जिसमें करीब 760 पैक्स और 60 से अधिक जिला मार्केटिंग समितियां भागीदार होंगी। इससे राज्य के 1.5 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस पहल से आईटीबीपी को न केवल गुणवत्ता के साथ एक सुनिश्चित मात्रा में नियमित रूप से सप्लाई हो रही, बल्कि किसानों की समृद्धि का मार्ग भी खुला है। ■

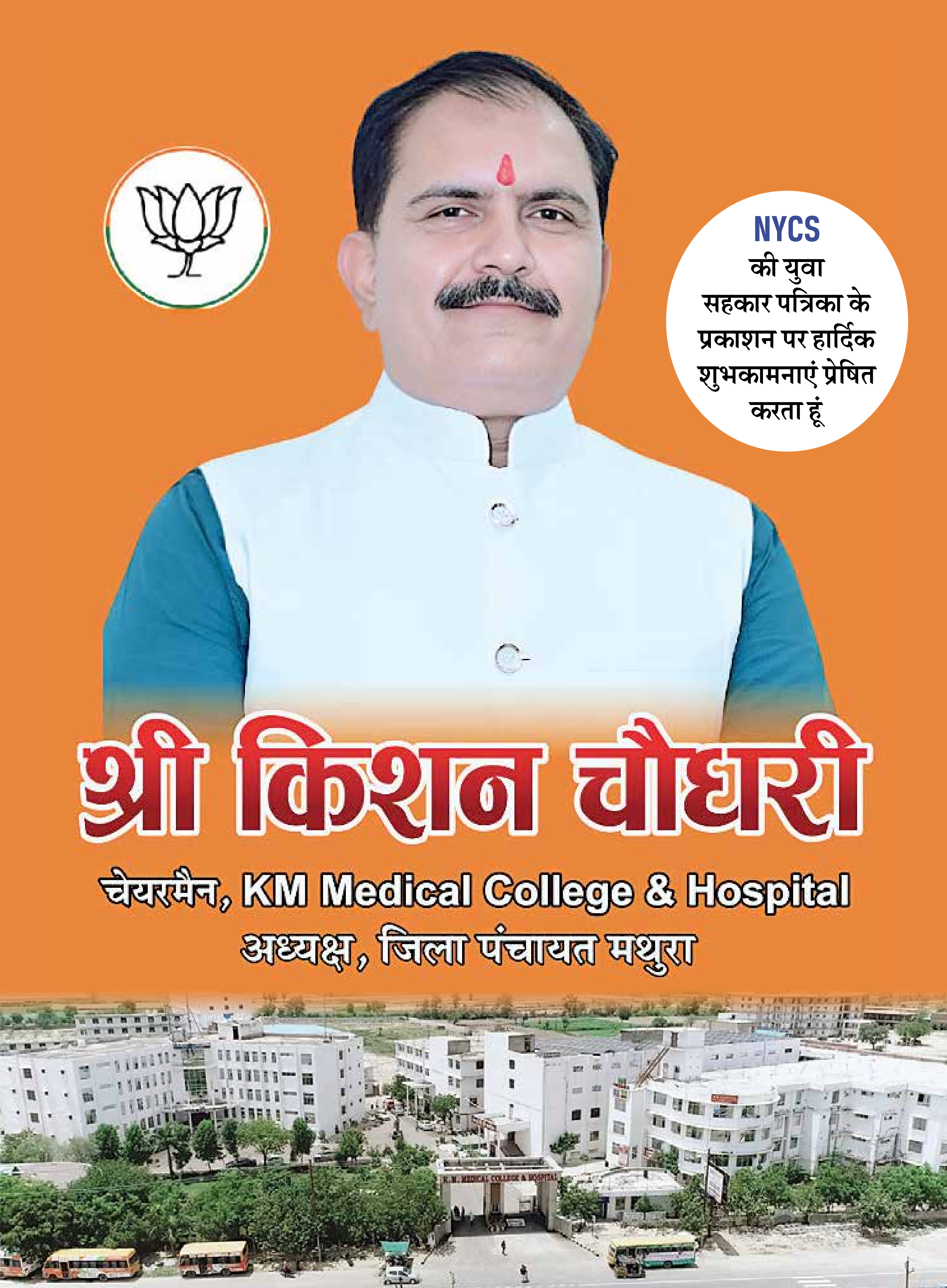
NYCS
की युवा
सहकार पत्रिका के
प्रकाशन पर हार्दिक
शुभकामनाएं प्रेषित
करता हूं
श्री किशन चौधरी
चेयरमैन, KM Medical College & Hospital
अध्यक्ष, जिला पंचायत मथुरा

National Yuva Co-operative Society Limited

NYCS

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.
Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.
Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B, Vardhman Janak Market, Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsindia.com

Together, let's build a brighter financial future!